प्रवाह

निर्भीक पत्रकारिता का आठवां दशक
स्थापना वर्ष : 1948

आप जिस तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, वह प्रभावित नहीं करती। आप इससे जो अनुभव पाते हैं, वही सब कुछ है। -सीन गेरेटी

यूपीएससी के ताजा विज्ञापन से लेटरल एंट्री को लेकर राजनीति बेशक गर्मा गई है, पर यह प्रशासनिक मुद्दा ज्यादा है, जिसकी पहली बार मांग 2005 में दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग ने की थी। चूंकि इसके पक्ष और विपक्ष, दोनों में तर्क दिए जा सकते हैं। ऐसे में जरूरी है कि इस पर संतुलित ढंग से विचार हो।

प्रशासनिक प्रश्न और राजनीति

संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) द्वारा हाल ही में केंद्र सरकार के 24 मंत्रालयों में संयुक्त सचिव, निदेशक और उप सचिव के 45 पदों पर लेटरल एंट्री के लिए योग्य भारतीय नागरिकों से आवेदन मंगाने से एक नया राजनीतिक विवाद तो पैदा हुआ ही है, लोक सेवाओं में लेटरल एंट्री व्यवस्था की जरूरत पर पुरानी बहस भी फिर से ताजा हो गई है। उल्लेखनीय है कि नौकरशाही में लेटरल एंट्री वह प्रक्रिया है, जिसके तहत सरकार मध्य व वरिष्ठ स्तर के पदों के लिए सरकारी सेवाओं के परंपरागत कैडर के बाहर से नियुक्ति करती है। नहीं भूलना चाहिए कि लेटरल एंट्री योजना की औपचारिक शुरुआत बेशक प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में हुई हो, जब 2018 में सरकार में संयुक्त सचिव व निदेशक जैसे वरिष्ठ पदों को भरने के लिए विशेषज्ञों से आवेदन मंगाए गए थे। लेकिन सबसे पहले इसकी जरूरत 2005 में प्रशासनिक सुधार के इरादे से वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में गठित दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग ने इस आधार पर जताई थी कि कुछ सरकारी दायित्वों के लिए विशेषज्ञ ज्ञान की जरूरत होती है, जो पारंपरिक लोक सेवाओं में उपलब्ध नहीं होता। आयोग के ताजा विज्ञापन में यह स्पष्ट उल्लेख होने के बावजूद कि ये सभी पद बेंचमार्क दिव्यांग श्रेणी के व्यक्तियों के लिए उपयुक्त हैं, विपक्षी दल इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण नहीं होने की वजह से आलोचना कर रहे हैं। दरअसल नियम यह कहते हैं कि सरकारी नौकरियों और विश्वविद्यालयों में आरक्षण की व्यवस्था 13-पॉइंट रोस्टर की नीति पर आधारित होती है, ताकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग व दिव्यांगों को मिलने वाले आरक्षण के अनुपात में संतुलन बना रहे। इसके अतिरिक्त, सरकार का यह भी तर्क है कि चूंकि आयोग के ताजा विज्ञापन के जरिये जो नियुक्तियां की जा रही हैं, उनका आधार डेपुटेशन है, लिहाजा इनमें कार्मिक मंत्रालय के सर्कुलर के मुताबिक, आरक्षण अनिवार्य नहीं होता। दरअसल राजनीति से हटकर देखें, तो लेटरल एंट्री एक प्रशासनिक मुद्दा है, जिसके पक्ष और विपक्ष दोनों में तर्क दिए जा सकते हैं, इसलिए इस मुद्दे पर संतुलित ढंग से विचार होना चाहिए। ऐसे वक्त में जब नौकरशाह ज्यादा वेतन वाली कॉरपोरेट नौकरियों की ओर जा रहे हों, तब बाहरी विशेषज्ञों के साथ प्रशासनिक गुणवत्ता को बनाए रखने की चुनौती भी है। यह सही है कि सरकार को विशेषज्ञता की जरूरत है, लेकिन इसके लिए अपनाई जा रही प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ यह भी जरूरी है कि प्रशासनिक संतुलन बना रहे और सिविल सेवकों का मनोबल भी प्रभावित न हो।

एआई का राष्ट्रवाद और आप

फेसबुक, अमेजन और गूगल से बड़ी क्रांति है एआई। इसका फायदा उठाने की होड़ में हर देश शामिल है, लेकिन कोई किसी पर निर्भर होना नहीं चाहता। इंटरनेट ने दुनिया जोड़ी थी। लेकिन एआई के इस राष्ट्रवाद में आपकी जिंदगी पर एआई का कितना असर होगा, यह इस पर निर्भर करेगा कि आप रहते कहां हैं।

कई देश चिंतित हैं कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई के विकास की दौड़ में वे कहीं पीछे न छूट जाएं। उनकी यह घबराहट जायज भी है। एआई बेहद तेजी से खुद को बदल रहा है। जल्द ही यह वैश्विक अर्थव्यवस्था को नया आकार दे सकता है, स्वचालन से नौकरियों को खतरे में डाल सकता है, वैज्ञानिक अनुसंधान को अभूतपूर्व बढ़ावा दे सकता है और यहां तक कि युद्ध छेड़ने के तरीके को भी बदल सकता है।

दुनिया के तमाम देशों का नेतृत्व चाहता है कि उनके देश के वैज्ञानिक इस एआई को काबू में करें और इसकी शक्तियों से देश को फायदा पहुंचाएं। लेकिन उन्हें यह भी डर है कि अगर उन्होंने अपने देश में सशक्त एआई ढांचे का निर्माण नहीं किया, तो उन्हें दूसरे देशों पर निर्भर रहना होगा। यह माहौल दरअसल एआई के क्षेत्र में राष्ट्रवाद को बढ़ावा दे रहा है। यह विचार तेजी से फैल रहा है कि एक देश को अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए अपनी तकनीकी विकसित करनी चाहिए। इस संबंध में विभिन्न देशों ने नए कानून और नियम तो बनाए ही हैं, नए गठबंधन भी बनाए हैं।

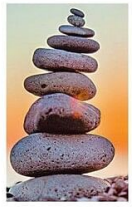

एडम सतारियानो
द न्यूयॉर्क टाइम्स

वैश्विक एआई की दौड़ में अमेरिका शायद सबसे आगे है, जो अपनी व्यापार नीतियों का कुछ इस तरह से इस्तेमाल कर रहा है, जिससे चीन को महत्वपूर्ण माइक्रोचिप्स से दूर किया जा सके। फ्रांस के राष्ट्रपति ने चैटबॉट और दूसरे टूल्स पर केंद्रित एक स्टार्ट-अप की तारीफ की है, जो फ्रेंच व दूसरी गैर-अंग्रेजी भाषाओं में अच्छा कर रहा है। सऊदी अरब में क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान एआई में अरबों डॉलर निवेश कर रहे हैं और अपने मुल्क को एआई का नया केंद्र बनाने के लिए अमेजन, आईबीएम और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। फ्रांस की सरकार की हालिया रिपोर्ट भी कहती है, 'हमें एआई से मिल रही चुनौती का सामना करना होगा, अन्यथा अपने भविष्य पर खुद का नियंत्रण खोने के जोखिम का सामना करना पड़ेगा।'

चैटजीपीटी का असर-एआई पर काबू पाने की दौड़ की शुरुआत एक बोर्ड गेम से हुई। वर्ष 2016 में गूगल के डीप माइंड द्वारा बनाए गए कंप्यूटरों ने एक बोर्ड गेम में एआई के मानवीय तरीके से व्यवहार करने से जुड़े हाई-प्रोफाइल मैच जीते और एआई की क्षमता का सफल प्रदर्शन किया। बीजिंग की स्वाभाविक ही इस पर नजर थी। चीन ने अरबों रुपये एआई के लिए अलग निकाल कर रख लिए और इस क्षेत्र में अगुआ बनने के लिए एक नीति तैयार की। चीन में अधिकारियों ने एआई को देश की विशाल निगरानी प्रणाली में एकीकृत किया और तकनीकी को सत्तावादी झुकाव दिया।

इसके बावजूद, जब 2022 में ओपन एआई ने चैटजीपीटी को लॉन्च किया, तब चीन की सर्वश्रेष्ठ कंपनियां तक हैरान रह गईं। कंपनियों में आगे बढ़ने की होड़ मच गई, जिन्होंने कुछ प्रगति भी की है। लेकिन सेंसरशिप और अन्य नियमों ने विकास में बाधा पहुंचाई। चैटजीपीटी ने और देशों को भी इस होड़ में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। यूएई, भारत और फ्रांस की कंपनियों ने अलग-अलग स्तर की सरकारी सहायता के साथ निवेशकों से अरबों डॉलर जुटाए हैं। कई देशों की सरकारों ने सब्सिडी दी है, अर्द्धचालक संयंत्रों के लिए फंड जुटाया है और नए व्यापार अवरोध तक खड़े किए हैं।

फायदे में अमेरिका-एआई के मामले में दूसरे देशों की तुलना में अमेरिका कहीं ज्यादा फायदे की स्थिति में है। अमेरिका के तकनीकी दिग्गज सबसे शक्तिशाली एआई को नियंत्रित करते हैं, उसके मॉडल बनाते हैं और उन्हें तैयार करने में दूसरे देशों से कहीं ज्यादा खर्च भी करते हैं। दुनिया भर के शीर्ष इंजीनियर और डेवलपर अब भी सिलिकॉन वैली में कॅरिअर बनाने की इच्छा रखते हैं। हालांकि यहां भी कुछ नियम एआई के विकास में बाधक बन रहे हैं।

लेकिन यह नहीं भूला जा सकता कि कीमती एआई चिप्स तक अमेरिकी कंपनियों की पहुंच आसान है, क्योंकि इनमें से ज्यादातर कैलिफोर्निया में ही तैयार की जाती हैं। अमेरिका इन चिप्स का उपयोग चीनी प्रतिस्पर्धा पर काबू पाने के लिए कर रहा है। वर्ष 2022 में अमेरिका ने ऐसे नियम लागू किए, जिनसे चीन इन चिप्स को न हासिल कर सके, जिनके बगैर वहां की कंपनियां अपनी गति बनाए नहीं रख सकतीं।

लेकिन बात सिर्फ चीन तक ही सीमित नहीं है। अमेरिका दूसरे देशों के साथ भी अपनी चिप्स-रणनीति खेल रहा है। अप्रैल, 2022 में माइक्रोसॉफ्ट ने अमेरिकी सरकार के साथ काम करते हुए सऊदी अरब की एक कंपनी को मदद दी, लेकिन यह शर्त भी रखी कि उसे चीन की तकनीकी का उपयोग बंद करना होगा।

अब आगे क्या-तकनीकी के इतिहास से जो हमने सीखा है, वही एआई के विकास से पैदा होने वाले संकटों की ओर इशारा करता है। सभी देशों ने देखा है कि गूगल, अमेजन और फेसबुक जैसी अमेरिकी कंपनियों ने समाज पर सिर्फ बेहतर असर ही नहीं डाला है। अब वे यानी अमेरिका एआई को अलग ढंग से विकसित करना चाहते हैं। उद्देश्य महज इतना है कि गोपनीयता से समझौता किए बगैर स्वास्थ्य व शिक्षा जैसे क्षेत्रों में तकनीकी के उपयोग के फायदों को लिया जाए।

एआई के फायदों को सभी देश अच्छी तरह समझ रहे हैं, लेकिन समस्या इसके विनियमन को लेकर है। पिछले वर्ष यूरोपीय संघ ने उन क्षेत्रों में एआई के उपयोग को सीमित करने के लिए एक कानून पारित किया था, जिन्हें मानवाधिकारों और सुरक्षा के लिए सबसे जोखिमपूर्ण माना गया है। अमेरिका ने कंपनियों से डीपफेक के प्रसार को सीमित करने की मांग की है। चीन में सरकार चैटबॉट जो कह सकते हैं, उसे सेंसर कर रही है।

जाहिर है कि एआई राष्ट्रवाद पूरी दुनिया को जोड़ने वाले इंटरनेट के विघटन का हिस्सा है, जहां सेवाएं स्थानीय कानूनों व राष्ट्रीय हितों के आधार पर भिन्न होती हैं। स्पष्ट है कि एआई राष्ट्रवाद के तहत, आपकी जिंदगी पर एआई का असर इस पर निर्भर करेगा कि आप किस जगह रह रहे हैं।

©The New York Times 2024

जीवन धारा

वेन डब्ल्यू डायर

आत्मा के मूल रूप में व्यक्ति आत्मा की उपस्थिति को पहचानना शुरू करता है। यही अदृश्य ज्ञान है, जो हमारे भीतर दया और प्रेम को जन्म देता है।

प्रेम की खोज ही जीवन की महत्वाकांक्षा होनी चाहिए

महत्वाकांक्षा के बारे में हमें जीवन भर विरोधाभासी संदेश और ज्ञान दिए जाते हैं। एक तरफ हमें बताया जाता है कि यह एक सकारात्मक गुण है, जो हमें प्रेरित करता है और लक्ष्य की ओर बढ़ने का संकेत देता है। दूसरी ओर, महत्वाकांक्षा को अक्सर अहंकार और प्रभुत्व की स्वीकृति के साथ-साथ दूसरों की भलाई के लिए चिंता की कमी के रूप में भी देखा जाता है। महत्वाकांक्षा के विचार को समझने का एक तरीका यह है कि इसे चार प्रमुख आदर्शों के माध्यम से देखा जाए। सबसे पहले, एक एथलीट के आदर्श को लें, जिसके जीवन के पहले चरण में महत्वाकांक्षा लगभग पूरी तरह से शरीर पर केंद्रित होती है। यह वयस्क जीवन का वह समय होता है, जब आपका प्राथमिक ध्यान आपकी उपस्थिति पर होता है। जैसे कि, मैं कितना अच्छा कर सकता हूं, मैं कितना मजबूत हूं... आदि। यहां महत्वाकांक्षा का मतलब है अपने शरीर के दिखने और वह क्या कर सकता है, के आधार पर खुद का मूल्यांकन करना।

वयस्क जीवन के अगले चरण में महत्वाकांक्षा उन विचारों पर केंद्रित होती है, जो एक योद्धा पर हावी होते हैं, जिसका लक्ष्य दुनिया को जीतना और उन लोगों से आगे निकलना है, जो रास्ते में आ सकते हैं। यह वक्त लक्ष्य निर्धारित करने, रणनीति बनाने, अध्ययन करने और जीवन में विजयी होने के लिए योजनाएं बनाने का होता है। योद्धा कड़ी मेहनत और लगन से अभ्यास करता है, दूसरों की कमजोरियों को पकड़ता है और तभी संतुष्ट होता है, जब वह अपने प्रतिद्वंद्वियों को मात दे देता है। बाकी सभी लोग ऐसे होते हैं, जिन्हें किसी न किसी तरह से परास्त किया जाना चाहिए। यह एक ऐसा आदर्श है, जिसमें कुछ लोग अपना पूरा जीवन जीते हैं और मर जाते हैं। एथलीट और योद्धा के लिए आंतरिक मंत्र है- 'इसमें मेरे लिए क्या है'। लेकिन एक राजनेता के संदर्भ में आंतरिक मंत्र बदल जाता है, और वह यह कि 'मैं कैसे सेवा कर सकता हूं'। यहां महत्वाकांक्षा दूसरों के जीवन में बदलाव लाने के बारे में है। इसी तरह होता है आत्मा का आदर्श। यह जीवन का वह समय होता है, जब आप यह महसूस करना शुरू करते हैं कि आप एक अनंत आध्यात्मिक प्राणी हैं, जो मानवीय जीवन का अनुभव कर रहा है। यहां आपकी महत्वाकांक्षा आपके दिव्य स्वभाव को भगवान के अंश के रूप में चित्रित करने की इच्छा की ओर स्थानांतरित होने लगती है, बशर्ते आप चाहें। ब्रह्मांड का रचनात्मक स्रोत अपने हाथों से केवल एक ही काम करता है, बिना किसी प्रतिफल की इच्छा के देना। आत्मा के मूल रूप में व्यक्ति आत्मा की उपस्थिति को पहचानना शुरू करता है। यही अदृश्य ज्ञान है, जो हमारे भीतर दया और प्रेम को जन्म देता है। मूल रूप में व्यक्ति अंततः समझ जाता है कि हमारी सारी महत्वाकांक्षा अब इस अंतिम सत्य को जीने की कोशिश में है कि जो भी प्रश्न हो, उसका उत्तर सिर्फ प्रेम ही है।

सकारात्मक महत्वाकांक्षा रखें

सूत्र

महत्वाकांक्षा सकारात्मक भी होती है और नकारात्मक भी। यदि महत्वाकांक्षा सकारात्मक है, तो वह हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, लेकिन नकारात्मक महत्वाकांक्षा हमें अहंकार ग्रस्त एवं आत्मकेंद्रित बनाती है। इसलिए हमारी महत्वाकांक्षा ऐसी हो, जिसमें दूसरों के लिए दया और प्रेम का भाव हो।

दूसरा पहलू

बताया जाता है कि रोम के सैनिकों ने जब पहली बार युद्ध के मैदान में हाथियों का सामना किया, तो वे डर गए।

रोम के सैनिकों को कैसे मिली हाथी से 'डर' पर विजय

क्षण भर के लिए कल्पना कीजिए कि आप युद्धरत रोम के सैनिक हैं। लड़ाई के बीच में ही आपका सामना चिंघाड़ने वाले विशाल प्राणी से हो जाए, जिसे आपने पहले कभी नहीं देखा हो। उसके मुंह के दोनों ओर नुकीले दांत निकले हों और उस पर हथियारबंद लोग सवार हों, जो तेजी से आपके साथियों को कुचलता हुआ आपकी ओर आ रहा हो। बताया जाता है कि रोम के सैनिकों ने जब पहली बार युद्ध के मैदान में हाथियों का सामना किया, तो वे डर गए। युद्ध में जानवरों का इस्तेमाल क्रूरता है, लेकिन रोम के हेलेनिस्टिक साम्राज्य और कार्थाजियन युद्ध में हाथियों का उपयोग करते थे।

माइकल बी चार्ल्स

सिकंदर उत्तरी भारत में युद्ध के बाद हाथियों को भूमध्यसागरीय दुनिया में वापस ले गए, जहां सदियों से हाथियों का इस्तेमाल युद्ध में होता रहा था।

सिकंदर महान उत्तरी भारत में युद्ध के बाद हाथियों को भूमध्यसागरीय दुनिया में वापस ले गए, जहां सदियों से हाथियों का इस्तेमाल युद्ध में किया जाता रहा था। 326 ईसा पूर्व सिकंदर का सामना भारत में हाथियों से सुसज्जित सेना से हुआ और वह हाथियों से प्रभावित हुआ था। इस तरह प्राचीन भूमध्यसागरीय दुनिया का हाथियों के प्रति आकर्षण बढ़ा। सिकंदर की मौत के बाद सीरिया के सेल्यूकिड्स, मिस्र के टॉलेमीज और मैसेडोनिया के एंटीगोनिड्स ने उत्साहपूर्वक एशियाई हाथियों को अपनी सेना में शामिल किया। इनमें ज्यादातर हाथियों को भारत से लाया गया, हालांकि मिस्र के टॉलेमीज ने अफ्रीकी हाथियों को अपनी सीमा सुरक्षा में लगा दिया था, क्योंकि उनके विरोधी सेल्यूकिड्स ने उन्हें एशियाई हाथियों की आपूर्ति नहीं होने दी।

बाद में रोम के सैनिकों ने हाथियों का सामना मिसाइलों से किया, नतीजतन हाथियों ने पीछे की ओर घूमकर अपने ही सैनिकों पर हमला शुरू कर दिया। इस तरह रोम के सैनिकों को हाथियों की कमजोरी का पता चला।

एक यूनानी राजा ने अपनी सेना को हाथियों से सुसज्जित किया था। वह एपिरस का राजा पाइरहस था, जो रोम से लड़ाई में वहां की सेना का परिचय हाथियों से कराया। पाइरहस का रोम से कई बार युद्ध में सामना हुआ। उसकी सेना ने 280 ईसा पूर्व में टेरेंटम से बहुत दूर दक्षिणी इटली के हेराक्लीया में रोम को हराया था। पाइरहस के हाथियों ने रोम के घुड़सवारों को भयभीत कर दिया था। उसने 279 ईसा पूर्व में फिर से रोमनों को परास्त किया। पाइरहस 275 ईसा पूर्व में फिर से दक्षिणी इटली में रोम से लड़ने पहुंचा, लेकिन इस बार रोम के सैनिक ज्यादा सतर्क थे। रोम के सैनिकों ने पाइरहस के हाथियों का सामना मिसाइलों से किया, नतीजतन मिसाइलों से परेशान हाथियों ने पीछे की ओर घूमकर पाइरहस के सैनिकों पर ही हमला शुरू कर दिया। इस तरह रोम के सैनिकों को हाथियों की कमजोरी का पता चला। रोम के सैनिकों को पता चल गया कि हाथी सिर्फ दुश्मनों को ही नहीं, अपनी सेना को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। *(कन्वर्सेशन से)*

आंकड़े

शीर्ष ब्रॉडबैंड

मई, 2024 के आंकड़ों के मुताबिक, हमारे देश में सबसे बड़ा ब्रॉडबैंड सेवा प्रदाता रिलायंस जियो है, जिसकी हिस्सेदारी आधे से अधिक है।

रिलायंस जियो	52.04%
भारती एयरटेल	29.74%
वोडा आइडिया	13.61%
बीएसएनएल	2.73%
अन्य	1.88%

आंकड़े प्रतिशत में, 31 मई, 2024 तक के | स्रोत : TRAI

मनुष्य का स्वभाव हर समय बदलता रहता है। जरूरी नहीं कि आज वाली अवस्था कल भी रहे। परिवर्तन ही तो जीवन है।

परिवर्तन ही जीवन है

रामकृष्ण परमहंस के शिष्य मास्टर कई दिनों से एक ही समय पर उनके दर्शन के लिए निरंतर आ जाते थे। मास्टर उन्हें समाधि की अवस्था में भाव-विभोर होकर देखते रहते थे। लेकिन आज जब उन्होंने स्वामी जी के कमरे में प्रवेश किया, तो माहौल बिल्कुल अलग था। श्रीरामकृष्ण अपने कमरे में एक तख्त पर बैठे थे। पास ही चटाई पर नरेंद्र, भवनाथ तथा एक-दो अन्य लोग बैठे थे। सभी हंसी-मजाक कर रहे थे।

मास्टर को देखते ही स्वामी जी बोले, यह देखो, ये फिर आ गए। इस पर सभी हंसने लगे। स्वामी जी ने मजाक करते हुए कहा, एक मोर को किसी ने चार बजे अफीम खिला दी। दूसरे दिन भी वह अफीमची मोर वहां ठीक चार बजे पहुंच गया। उसी मोर की तरह यह भी ठीक समय पर पहुंच गया है। इस पर सभी फिर हंसने लगे, लेकिन मास्टर ने कहा, आप ठीक कह रहे हैं, घर में जाता हूं, तो मन यहीं लगा रहता है। मास्टर स्वामी जी को देखकर सोचने लगे कि कितना अद्भुत चरित्र है इनका। कल जब इन्हें देखा था, तो ये समाधि की गहन अवस्था में थे और आज पांच वर्ष के बालक की तरह हंस रहे हैं। साकार और निराकार के बारे में समझा रहे हैं, सत्य और असत्य का ज्ञान देते हैं। सच ही कहा है, मनुष्य का स्वभाव हर समय बदलता रहता है। जरूरी नहीं कि आज वाली अवस्था कल भी रहे। परिवर्तन ही तो जीवन है।

अंतर्यात्रा
संकलित

अमर उजाला

पुराने पन्नों से — 21 सितंबर, 1992

भ्रष्टाचार के खात्मे के लिए नई व्यवस्था

भ्रष्ट अफसरों की दबी फाइलें खोल रहा हूं

(कार्यालय प्रतिनिधि)

आगरा, 20 सितम्बर। राज्य सरकार उन भ्रष्ट अधिकारियों की फाइल फिर से खोल रही है, जिनके विरुद्ध जांच के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है।

मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने जनसभा में यह बात कही। उन्होंने कहा कि मेरी सरकार में कोई भी भ्रष्ट बच नहीं पायेगा। अब तक जूनियर इंजीनियर तक कार्रवाई होती थी, पर हमने हाल में एक चीफ इंजीनियर को हथकड़ी लगवाकर जेल भिजवाया। वह रिश्वत लेते पकड़ा गया था।

मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने कहा कि राज्य सरकार भ्रष्ट अधिकारियों की फाइल फिर से खोल रही है। उन्होंने कहा कि दंड से भ्रष्टाचार कम किया जा सकता है, पर पूरी तरह खत्म नहीं। हम पूरी तरह खात्मे के लिए नई व्यवस्था लागू कर रहे हैं।

'छंदय-मोड' में श्रीलंका

21 सितंबर को श्रीलंका में राष्ट्रपति चुनाव होगा। यह चुनाव श्रीलंका के भविष्य, भारत तथा हिंद महासागरीय क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है।

सुधीर सक्सेना | पड़ोस

छंदय यानी चुनाव। सिंहली-अंग्रेजी युग्म रचें, तो होगा छंदय-मोड। हमारा पड़ोसी राष्ट्र श्रीलंका इन दिनों छंदय मोड में है। एक महीने बाद 21 सितंबर को करीब एक करोड़ 70 लाख मतदाता विषम परिस्थितियों से गुजर रहे द्वीप-राष्ट्र का नया राष्ट्रपति चुनेंगे! बिसात बिछ चुकी है। पासे फेंके जा चुके हैं। वातावरण आवेशित है। दुविधा और संभ्रम की स्थिति है। हालांकि ज्यादातर खिलाड़ी सुपरिचित हैं।

यों तो एक अनार के लिए बीमारों की संख्या 39 है, किंतु मुकाबले में मुख्यतः चार खिलाड़ी हैं। ये चार खिलाड़ी हैं-अनेक दलों का समर्थन प्राप्त, निवर्तमान राष्ट्रपति निर्दलीय प्रत्याशी रानिल विक्रमसिंघे, समागी जन बालवेगया के सजिथ प्रेमदासा, श्रीलंका पोदुजाना पेरामुना के नमल राजपक्षे और जनता विमुक्ति पेरामुना के अनुरा कुमारा दिसानायके। इनमें पांच बार प्रधानमंत्री रह चुके 75 वर्षीय रानिल वरिष्ठतम हैं, जबकि नमल की आयु सबसे कम 38 वर्ष है।

गौरतलब है कि श्रीलंका की राजनीति में राजपक्षे परिवार को स्वेच्छाचारी और एकाधिकारवादी माना जाता है। विगत संसदीय चुनाव में उसके पांच सदस्य जीते थे। महिंदा राजपक्षे बने प्रधानमंत्री, अनुज त्रयी गोटबाया राष्ट्रपति, चमल सिंचाई मंत्री, बेसिल वित्तमंत्री और पुत्र नमल खेलमंत्री। वर्ष 2022 में व्यापक जनाक्रोश राजपक्षे परिवार के पतन का कारण बना। यों तो रानिल सत्ताच्युत गोटबाया राजपक्षे की पसंद थे, लेकिन वक्त ने रानिल पर गोटबाया के भरोसे की चूलें हिला दी है। इसलिए उन्होंने युवा नमल को मैदान में उतारा है। विधि में स्नातक नमल एसएलपीपी के 'पोस्टर ब्वॉय' हैं। उन्हें मिले वोट से पता चलेगा कि अधिनायक-वृत्ति और स्वेच्छाचारिता के बावजूद श्रीलंकाई लोग राजपक्षे परिवार को कितना पसंद करते हैं?

पिछले दो दशकों से श्रीलंका में सत्ता की चाबी राजपक्षे परिवार के हाथों में है। लेकिन अरागलिया विद्रोह ने राजपक्षे परिवार के पांवों तले से जमीन खींच ली। एकबारगी लगा कि महिंदा पलायन को बाध्य होंगे, लेकिन कूचे से बेआबरू होकर निकलने की अटकलों के बीच उन्हें पूर्वोत्तर प्रांत के नौसैनिक अड्डे त्रिंकोमाली में मुकम्मल सुरक्षा मिल गई। राजपक्षे घराना फौजी हिफाजत में तबसे वहीं रह रहा है।

श्रीलंका में चीन की रुचि और भारत को घेरने की उसकी कोशिशें किसी से छिपी नहीं हैं। चीन से राजपक्षे का मोह अब भी कायम है। 27 जून, 2024 को महिंदा चीन के विदेश मंत्री वांग के न्यौते पर बीजिंग गए थे। वहां वह चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिले। फिर उनकी चीनी प्रधानमंत्री ली छियांग से ऋण पुनर्गठन मसौदे पर भी चर्चा हुई। कहना कठिन है कि महिंदा और चीनी नेताओं के बीच चुनाव और भावी राजनीति को लेकर क्या खिचड़ी पकी, लेकिन इस बाबत महिंदा की चुप्पी अटकलें पैदा करती है।

भारत और श्रीलंका के रिश्ते गर्भनाल सरीखे हैं। जातीय और सांस्कृतिक संदर्भ भारत-श्रीलंका मैत्री को दृढ़ आधार प्रदान करते हैं। श्रीलंका का भारत के लिए अतिरिक्त सामरिक महत्व भी है। भारत ने भयावह वित्तीय संकट का सामना करने में कोलंबो की भरपूर मदद की। श्रीलंका के घटनाक्रम पर भारत की पैनी निगाह है। यही वजह है कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कोलंबो जाने पर महिंदा राजपक्षे से मुलाकात और चर्चा की। बीते फरवरी में जनता विमुक्ति पेरामुना के नेता अनुरा कुमारा दिसानायके दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री जयशंकर से मिले थे।

अनुरा दिसानायके वामपंथी सोच के मुखर नायक हैं और इस छंदय-द्वंद्व में चमकीली संभावना बनकर उभरे हैं। बहुत संभव कि वह कोलंबो की सत्ता की पेचीदा लड़ाई में दिल्ली की परोक्ष पसंद बनकर उभरें। अनुरा राजधानी कोलंबो से सांसद हैं और भ्रष्टाचार-विरोधी मुहिम के पुरोधा भी हैं। भौतिकी में स्नातक अनुरा एक श्रमिक के बेटे हैं और वर्ष 2015-18 में मैत्रीपाल सिरिसेना के काल में मुख्य विपक्षी सचेतक रहे। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से रिश्तों को लेकर उनका रुख रानिल से सर्वथा भिन्न है।

रानिल की चमक और खनक अब पहले जैसी नहीं रही। एक तो उनकी छवि राजपक्षे-कुनबे के 'पिछलग्गू' की है, दूसरे मितव्ययिता के सख्त उपायों के कारण वह अलोकप्रिय हो चुके हैं। बहरहाल, लड़ाई रोचक है, श्रीलंका के भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण और भारत तथा हिंद महासागरीय क्षेत्र के लिए बहुत मानीखेज। बड़ी बात यह है कि इस चुनाव में श्रीलंका की युवा-शक्ति और सोशल मीडिया निर्णायक भूमिका निभा रहा है।

edit@amarujala.com

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 17 अंक 158

विशेषज्ञों की नियुक्ति

संघ लोक सेवा आयोग ने संयुक्त सचिव और निदेशक/उपसचिव स्तर के 45 पदों के लिए तीन वर्ष की अवधि के अनुबंध के वास्ते आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस अवधि को बढ़ाकर पांच वर्ष तक किया जा सकता है। यह दिखाता है कि केंद्र सरकार अफसरशाही में लैटरल एंट्री (बाहरी प्रवेश) को लेकर निरंतर प्रतिबद्ध है। विभिन्न विभागों और मंत्रालयों मसलन इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय, वन एवं जलवायु परिवर्तन तथा वित्तीय सेवा विभाग आदि में आमंत्रित ये रिक्तियां विशेषज्ञों के लिए हैं। उदाहरण के लिए केंद्र सरकार वित्तीय सेवा विभाग में एक संयुक्त सचिव खोज रही है ताकि डिजिटल इकॉनमी, फिनटेक और साइबर सुरक्षा पर ध्यान दिया जा सके।

ऐसी कई वजह हैं जिनके चलते सरकार को चुनिंदा पदों पर विशेषज्ञों को नियुक्त करना चाहिए और इस विचार को लेकर कई बार चर्चा हो चुकी है। उदाहरण के लिए छठे वेतन आयोग ने कहा था कि व्यवस्था में सुधार के लिए वरिष्ठ पदों पर लैटरल एंट्री के अलावा अधिक परिणामोन्मुखी रुख अपनाया जाना चाहिए।

इसके अतिरिक्त नीति आयोग के तीन वर्षीय एजेंडे और शासन को लेकर सचिवों के क्षेत्रीय समूह ने 2017 में अपनी रिपोर्ट में यह सिफारिश की थी कि नई प्रतिभाओं को लाने और जनशक्ति की उपलब्धता बढ़ाने के लिए मध्यम और वरिष्ठ स्तर पर लोगों शामिल किया जाए। सरकार ने इस माह के आरंभ में संसद में जो जवाब दिया था उसके मुताबिक बीते पांच सालों में संयुक्त सचिव, निदेशक और उपसचिव के स्तर पर ऐसी 63 नियुक्तियां की गई हैं। फिलहाल ऐसे 57 अधिकारी विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में पदस्थ हैं।

लैटरल एंट्री की शुरुआत की वजह सबको पता है। अर्थव्यवस्था का आकार और जटिलता बढ़ने के साथ प्रभावी नीतिगत हस्तक्षेप करने के लिए अक्सर विभिन्न क्षेत्रों की जानकारी की आवश्यकता होगी। सरकार के शीर्ष पदों पर अक्सर भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी पदस्थ रहते हैं। हालांकि कुछ अधिकारी समय के साथ विषय विशेष का ज्ञान हासिल कर लेते हैं। इस सेवा की आम मांग सामान्य प्रकृति की जानकारी रखने की है जो आवश्यक नहीं कि नीति निर्माण के बदलते परिदृश्य में हमेशा कारगर ही साबित हो। चाहे जो भी हो, आईएएस अधिकारियों की कुल तादाद स्वीकृत स्तर से काफी कम है। नीति निर्माण के स्तर पर नियुक्तियों में अन्य सेवाओं के अधिकारियों को शामिल करके टैलेंट पूल बढ़ाने की जरूरत है। यह काम कुछ हद तक किया भी जा रहा है। निजी क्षेत्र के विशेषज्ञों के लिए ऐसे पदों को खोलने से उपयुक्त उम्मीदवार मिलने की संभावना बढ़ जाएगी।

इसके अलावा चूंकि निजी क्षेत्र के लोगों को सीमित समय के लिए प्रवेश मिलेगा इसलिए सरकार जरूरत के मुताबिक निरंतर नई प्रतिभाओं को शामिल कर सकती है। उसे जरूरत पड़ने पर कार्यकाल बढ़ाने का विकल्प भी खुला रखना चाहिए। राज्य सरकारों को भी निजी क्षेत्र की प्रतिभाओं को इसी तरह नियुक्त करना चाहिए। बहरहाल सरकार की इस योजना के कामयाब होने के लिए यह आवश्यक है कि मौजूदा अफसरशाही उनके साथ सहयोग के साथ काम करे। इसके लिए तथा लैटरल एंट्री पाने वालों को व्यवस्था में स्वीकार्य बनाने के लिए सरकार को कम से कम दो काम करने होंगे: पहला, नियमित रूप से निजी क्षेत्र के लोगों को शामिल करके इस व्यवस्था का संस्थानीकरण करना होगा। दूसरा, उसे इस विषय में उपयुक्त संवाद करना होगा और दिखाना होगा कि कैसे इस व्यवस्था से लाभ हो रहा है। विपक्ष ने आरक्षण का हवाला देते हुए इस कदम की आलोचना की है जिससे बचा जाना चाहिए था। ये सीमित अवधि के और विशेषज्ञता वाले पद हैं और आरक्षण की बाध्यता इसके उद्देश्य को प्रभावित कर सकती थी। बहरहाल अगर सरकार अफसरशाही के विभिन्न स्तरों पर नियम के मुताबिक आरक्षण का उचित प्रतिनिधित्व बरकरार रखे तो बेहतर होगा।

मुद्रास्फीति लक्ष्य खाद्य वस्तु बिना कारगर नहीं

किसानों के हित सुरक्षित रखना जरूरी है मगर इसके लिए एक बेहतर विकल्प की आवश्यकता है अन्यथा मौद्रिक एवं वृहद आर्थिक स्थितियां संभालना और भी जटिल हो जाएगा। बता रहे हैं जनक राज

पिछले महीने संसद में पेश आर्थिक समीक्षा में सुझाया गया है कि भारत में मुद्रास्फीति नियंत्रण से जुड़े लक्ष्य का निर्धारण करते समय खाद्य वस्तुओं पर विचार नहीं करना चाहिए। इसके पीछे तर्क दिया गया है कि मुद्रास्फीति की गणना में खाद्य वस्तुएं शामिल करने से किसानों को उनके उत्पाद के मूल्य बढ़ने का फायदा नहीं मिल पाता है। समीक्षा में तर्क दिया गया है कि आपूर्ति में व्यवधान के कारण बढ़ी महंगाई नियंत्रित करने के लिए अल्प अवधि के मौद्रिक उपाय नुकसानदेह हो सकते हैं। परंतु यह सुझाव कुछ अहम बातें सामने लाता है।

पहली बात, यह सच है कि मौद्रिक नीति मांग के प्रबंधन का जरिया है और खाद्य मुद्रास्फीति में वृद्धि पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। किंतु लगातार ऊंची खाद्य मुद्रास्फीति के 'दूसरे चरण के प्रभाव' (दूरगामी प्रभाव) नियंत्रित करने में मौद्रिक नीति महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर आपूर्ति में व्यवधान अस्थायी है तो यह बड़ी समस्या नहीं है और मौद्रिक नीति इसे नजरअंदाज कर सकती है क्योंकि कारण दूर होते ही बढ़ी मुद्रास्फीति अपने शुरुआती स्तर पर आ जाएगी। यह भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि मौद्रिक नीति के अंतर्गत उठाए गए कदमों का असर देर से पता (अमूमन एक वर्ष से अधिक समय) चलता है। लिहाजा जब तक मौद्रिक नीति का असर महसूस किया जाता है तब तक मुद्रास्फीति अपने शुरुआती स्तर पर आ सकती है। अगर आपूर्ति व्यवधान लंबे समय तक रहता है तो खाद्य मुद्रास्फीति का असर समूची मुद्रास्फीति पर भी दिखने लगता है। इसका कारण यह है कि लोग खाद्य मुद्रास्फीति को अन्य मुद्रास्फीति से भी जोड़ने लगते हैं। खाद्य वस्तुओं की कीमतें लंबे समय तक ऊंचे स्तरों पर रहती हैं तो 'दूसरे चरण का प्रभाव' बढ़ने लगता है।

भारत में अक्सर किसी न किसी खाद्य वस्तु की आपूर्ति में बाधा आती है। भारत में खाद्य मुद्रास्फीति का असर लोगों पर अधिक दिखता है क्योंकि इसे हरेक दिन महसूस किया जाता है, जबकि समग्र मुद्रास्फीति के साथ यह बात नहीं है। इसे देखते हुए भारत में 'दूसरे चरण का प्रभाव' अधिक दिखता है। हाल में कई ऐसे उदाहरण देखने को मिले हैं जब खाद्य मुद्रास्फीति लगातार ऊंची रहने का असर समग्र मुद्रास्फीति पर भी दिखा है। मुद्रास्फीति नियंत्रित करने के भारतीय रिजर्व बैंक के लक्ष्य में खाद्य मुद्रास्फीति शामिल की जाए या नहीं की जाए, दूसरे चरण के प्रभाव का जोखिम तो रहेगा।

दूसरी अहम बात यह है कि खाद्य वस्तुओं को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) से हटाने पर मौद्रिक प्राधिकरण के रूप में रिजर्व बैंक की विश्वसनीयता पर चोट पहुंच सकती है। सीपीआई में खाद्य वस्तुओं की हिस्सेदारी 45.8 प्रतिशत है। समग्र मुद्रास्फीति उन विभिन्न जरूरी वस्तुओं एवं सेवाओं के दाम में उतार-चढ़ाव का आकलन करती है, जिनका इस्तेमाल उपभोक्ता रोजमर्रा के जीवन में करते हैं। मुद्रास्फीति का आकलन करने वाला कोई तरीका अगर सीपीआई में आधी हिस्सेदारी रखने वाले खंड (खाद्य वस्तुएं) को बाहर रखता है तो यह जीवनयापन पर होने वाले कुल खर्च की बानगी नहीं दे सकता। परिवार खाद्य वस्तुओं पर भी खर्च करता है, इसलिए आम आदमी को यह समझाना आसान नहीं होगा कि रिजर्व बैंक उपभोग श्रेणी में आने वाली सभी वस्तुओं एवं सेवाओं में से आधे की ही परवाह क्यों करता है। समाज में आर्थिक रूप से पिछड़े लोग तो बढ़ी मुद्रास्फीति से प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के जरिये बच सकते हैं मगर समाज का एक बड़ा हिस्सा ऊंची खाद्य एवं समग्र मुद्रास्फीति का सामना करेगा। मुद्रास्फीति निर्धारण की प्रक्रिया से खाद्य वस्तुओं को बाहर रखने पर आम लोगों को यही लगेगा कि रिजर्व बैंक मूल्य स्थिरता के अपने संकल्प को कमजोर कर रहा है।

तीसरी महत्त्वपूर्ण बात यह है कि सीपीआई में अगर खाद्य वस्तुएं शामिल नहीं की जाएं तो यह स्थिति रिजर्व बैंक के लिए एक बड़ी चुनौती हो सकती है और संवादहीनता की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। उस स्थिति में चुनौती और बढ़ सकती है, जब समग्र मुद्रास्फीति और अखाद्य मुद्रास्फीति दर में अधिक अंतर रहता है। भारत में अक्सर ऐसा दिखता है। वास्तव में समग्र मुद्रास्फीति और प्रमुख मुद्रास्फीति (खाद्य वस्तुएं और ईंधन शामिल नहीं) दरों में बड़े अंतर को देखते हुए बैंक ऑफ थाईलैंड ने समग्र मुद्रास्फीति पर ध्यान केंद्रित किया और प्रमुख मुद्रास्फीति को छोड़ दिया। बैंक ऑफ थाईलैंड ने प्रमुख मुद्रास्फीति के लिए जो उपाय किए थे वे समग्र और प्रमुख मुद्रास्फीति में बहुत अंतर होने की स्थिति में जीवनयापन पर होने वाले वास्तविक खर्च को नहीं दर्शा पाते थे। बैंक ऑफ कोरिया ने भी 2007 से प्रमुख मुद्रास्फीति की जगह समग्र मुद्रास्फीति पर ध्यान केंद्रित कर दिया।

मुद्रास्फीति नियंत्रण की व्यवस्था अपनाने वाले सभी बड़े केंद्रीय बैंक मुद्रास्फीति की गणना समग्र मुद्रास्फीति के आधार पर करते हैं क्योंकि इसे समझना और समझाना आसान होता है। फिर भी मौद्रिक नीति तैयार करते वक्त किसी गलती से बचने के लिए रिजर्व बैंक सहित लगभग सभी केंद्रीय बैंक कुछ हद तक प्रमुख मुद्रास्फीति का भी प्रयोग करते हैं। इससे उन्हें अर्थव्यवस्था में व्यापक मुद्रास्फीति नियंत्रित करने में मदद मिलती है। मुद्रास्फीति नियंत्रित करने के ऐसे उपाय निहित मुद्रास्फीति दर (आपूर्ति में किसी तरह का व्यवधान नहीं होने पर सामान्य परिस्थितियों में मूल्य बदलाव की अपेक्षित दर) का आकलन करने के लिए इस्तेमाल होते हैं।

चौथी बात यह है कि समग्र मुद्रास्फीति का आकलन करने के तरीके से खाद्य वस्तुएं बाहर हुईं तो कई तरह के सवाल उठने लगेंगे और रिजर्व बैंक जिस सूचकांक को आधार बनाता है उसमें शामिल वस्तु एवं सेवाओं के चयन पर बहस शुरू हो जाएगी।

इस समस्या से निपटने का एक उपयुक्त तरीका यह है कि रिजर्व बैंक को मौद्रिक नीति के संचालन में अधिक सहूलियत दी जाए। इसके लिए बदलती परिस्थितियों को दर्शाने के मकसद से सीपीआई के विभिन्न घटकों के भार संशोधित करने होंगे। वर्ष 2022-23 के लिए घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण (एचसीईएस) मार्च 2024 में जारी किया गया, जिसमें प्रति व्यक्ति औसत मासिक उपभोग व्यय में खाद्य वस्तुओं का हिस्सा काफी कम हो गया। ग्रामीण इलाकों में यह 2009-10 के 57 प्रतिशत था किंतु 2022-23 में घटकर 47.5 रह गया। इसी तरह शहरी क्षेत्रों में इसी अवधि के दौरान यह 44.4 प्रतिशत से घटकर 39.2 प्रतिशत रह गया। लिहाजा सीपीआई सूची में विभिन्न घटकों के भार में संशोधन करने की जरूरत वाकई है। भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रगति के साथ लोगों की आय भी बढ़ रही है, इसलिए घरेलू उपभोग सूची में खाद्य वस्तुओं का भार और कम होना चाहिए। इसे देखते हुए सरकार को हर तीन वर्ष में सीपीआई का भार दुरुस्त करना चाहिए।

किसानों के हितों की रक्षा अवश्य होनी चाहिए मगर इसके लिए किसी बेहतर विकल्प की आवश्यकता है। मुद्रास्फीति का आकलन करने वक्त खाद्य वस्तुओं पर विचार नहीं करने से मौद्रिक एवं वृहद आर्थिक प्रबंधन और जटिल हो जाएगा।

(लेखक सोशल ऐंड इकनॉमिक प्रोग्रेस, नई दिल्ली में सीनियर फेलो हैं। वह रिजर्व बैंक के कार्यकारी निदेशक तथा मौद्रिक नीति समिति के सदस्य रह चुके हैं)

बैंक जमाएं: गलत दिशा में बढ़ती प्राथमिकताएं?

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास बैंकिंग क्षेत्र की में जमा वृद्धि धीमी होने पर चिंतित हैं। बैंकिंग उद्योग जमा में भी ऋण के बराबर वृद्धि दर हासिल करने में सबसे कठिन चुनौतियों से जूझ रहा है। 26 जुलाई तक सभी वाणिज्यिक बैंकों के पास कुल 211.93 लाख करोड़ की जमा थीं किंतु उनके द्वारा दिया गया ऋण 168.14 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया। इस वित्त वर्ष में अभी तक जमाओं में 3.5 फीसदी वृद्धि हुई है और ऋण में वृद्धि 2.3 फीसदी रही है। लेकिन पिछले एक वर्ष में जमा वृद्धि 10.6 फीसदी रही है, जो ऋण में हुई 13.7 फीसदी वृद्धि से काफी कम है। 2023 में लगभग इसी समय जमाओं में वृद्धि एक साल पहले की तुलना में 12.9 फीसदी थी और ऋण में वृद्धि 19.7 फीसदी थी। वर्ष 2022 में ये आंकड़े 9.2 फीसदी और 14.5 फीसदी थे।

जमाओं में वृद्धि जब ऋण वृद्धि से कम होती है तब बैंकों का ऋण-जमा (सीडी) अनुपात उच्च स्तर पर होता है। 100 रुपये की हर जमा राशि पर बैंकों को नकद आरक्षित अनुपात के तौर पर रिजर्व बैंक के पास 4.5 रुपये अवश्य रखना होते हैं और बाकी 18 रुपये का निवेश सरकारी बॉन्ड में करना होता है। इस कारण सैद्धांतिक रूप से बैंकों के पास 100 रुपये की हर जमा राशि में से कर्ज देने के लिए 78.5 रुपये बचते हैं। किंतु वास्तव में बॉन्ड में अधिक निवेश के कारण यह राशि अक्सर और भी कम होती है। यद्यपि बैंक इस पूंजी का इस्तेमाल ऋण देने के लिए बिल्कुल कर सकते हैं। जुलाई महीने के मध्य में बैंकिंग तंत्र का औसत सीडी अनुपात 79.39 फीसदी था, जो मार्च मध्य के 80.25 फीसदी से कम है।

जब जमा वृद्धि धीमी होती है तब बैंकों को वाणिज्यिक पत्र (सीपी) और जमा प्रमाणपत्र के जरिये बाजार से पूंजी जरूर जुटानी चाहिए। वित्त वर्ष 2024 में बैंकों ने जमा प्रमाणपत्र से 9.56 लाख करोड़ रुपये जुटाए, जो उससे पिछले वर्ष जुटाए गए 7.28 लाख करोड़ रुपये की तुलना में 31 फीसदी अधिक थे। इस तरह की रकम महंगी पड़ती है और वाणिज्यिक पत्र की अवधि तो और भी कम है।

पिछले साल कुल जमाओं में कम खर्च वाले चालू एवं बचत खातों (कासा) की हिस्सेदारी 43 फीसदी थी, जो उससे पिछले वर्ष के 45 फीसदी से कम है। फिलहाल इनकी हिस्सेदारी 41 फीसदी है। हालांकि यह बड़ी समस्या नहीं है क्योंकि 2010 के दशक के मध्य में कासा और भी कम था। किंतु बढ़ती होड़ के कारण बैंकों को जमा आकर्षित करने के नए तरीके ढूंढने ही होंगे।

बैंकिंग साख
तमाल बंद्योपाध्याय

ऊंची ब्याज दर जमा आकर्षित करने का पुराना तरीका है। कुछ लघु वित्त बैंक एक से दो वर्ष की सावधि जमा पर 8-9 फीसदी ब्याज दे रहे हैं और दूसरे बैंक इसी अवधि के लिए 6.5 फीसदी से 8 फीसदी ब्याज दे रहे हैं। वरिष्ठ नागरिकों को आम तौर पर आधा फीसदी अतिरिक्त ब्याज मिलता है और कुछ बैंक 80 वर्ष या इससे भी अधिक उम्र के नागरिकों को और भी ज्यादा ब्याज देते हैं।

दूसरे देशों की बात करें तो जिम्बाब्वे में बैंक जमाओं पर सबसे ज्यादा 110 फीसदी ब्याज दे रहे हैं। अर्जेंटीना 69.89 फीसदी ब्याज के साथ दूसरे स्थान पर है। शीर्ष 10 देशों में तुर्की (43.5 फीसदी), वेनेजुएला (36 फीसदी), उज्बेकिस्तान (18.4 फीसदी), सिएरा लियोन (15.75 फीसदी), मिस्र (14.49 फीसदी), कोलंबिया (13.21 फीसदी), मैडागास्कर (13 फीसदी) और मंगोलिया (11.6 फीसदी) शामिल हैं। इतना ऊंचा ब्याज उच्च मुद्रास्फीति की वजह से दिया जा रहा है। भारत की बात अलग है। यहां बैंकों को ज्यादा जमा आकर्षित करने के तरीके ढूंढने होंगे ताकि इसे ऋण वृद्धि के अनुरूप रखा जा सके। अन्यथा ऋण वृद्धि की रफ्तार धीमी होगी जिसका असर आर्थिक वृद्धि पर भी पड़ेगा।

विभिन्न श्रेणियां बनाने और अलग-अलग नामों से उनकी ब्रांडिंग करने के अलावा जमाओं में कुछ नया कम ही किया गया है। बाहरी बेंचमार्क से जुड़ी फ्लोटिंग दर वाली जमा योजनाएं लोकप्रिय नहीं हुईं। बचत करने वाले लोग अक्सर आवर्ती जमा चुनते हैं और किसी खास मकसद से हर महीने पैसे लगाते हैं। कई बैंक अब स्वीपिंग सुविधा की पेशकश भी कर रहे हैं जिसके तहत बचत खाते में मौजूद रकम एक खास सीमा से ऊपर जाने पर खुद ही सावधि जमा खाते में पहुंच जाती है और उस पर अधिक ब्याज मिलता है।

बचत खाते पर ब्याज दर 2011 में नियंत्रण मुक्त कर दी गई लेकिन अधिकतर सरकारी बैंक अब भी कम ब्याज दे रहे हैं। कुछ निजी बैंक चरणों में ब्याज दर बढ़ाते हैं और जमा खाते में रकम बढ़ने पर ब्याज दर भी बढ़ती है। हालांकि चालू खाते पर ब्याज नहीं मिलता मगर खाताधारकों को कुछ फायदे मिलते हैं जैसे ओवरड्राफ्ट (खाते में रकम नहीं होने पर भी निकासी) सुविधा मिलती है। वाणिज्यिक बैंकों में बकाया रुपये की सावधि जमा की भारित औसत दर जून 2022 में 5.13 फीसदी थी। यह जून 2023 में बढ़कर 6.47 फीसदी और जून 2024 में 6.91 फीसदी हो गई। जमाकर्ताओं को लुभाने के लिए बैंक ऊंची ब्याज दर के अलावा कर ही क्या सकते हैं?

सीतारमण ने बैंकों से छोटी जमाएं जुटाने पर ध्यान देने को कहा है। इत्तफाक से लगभग एक सदी पहले वर्ष 1928 में सिंडिकेट बैंक (जिसका अप्रैल 2020 में केनरा बैंक में विलय हो गया) ने पिग्मी जमा योजना (रोजाना जमा योजना) शुरू की। बैंक के एजेंट किसानों और दुकानदारों के पास जाकर पैसे इकट्ठे थे। जमाकर्ता रोजाना, हर हफ्ते या हर महीने केवल चवन्नी यानी 25 पैसे भी जमा कर सकता था। रोजाना 25 पैसे की बचत 3.5 फीसदी सरल ब्याज दर के साथ सात वर्ष में 700 रुपये बन जाती थी।

सिंडिकेट बैंक ने अपने कर्मचारियों को खाली वक्त में पिग्मी बैंक का जमा एजेंट बनने के लिए प्रोत्साहित किया। वर्ष 1960 तक बैंक की शुद्ध जमाओं में पिग्मी जमाओं का योगदान 21 फीसदी हो गया था। मगर आज बैंक इस मॉडल पर नहीं चल सकते क्योंकि यह बहुत खर्चीला होगा। इन दिनों धारणा है कि बचतकर्ता पूंजी लगाने के लिए शेयर (सीधे तौर पर या म्युचुअल फंड के जरिये), रियल एस्टेट या सोना समेत विभिन्न विकल्प तलाश रहे हैं। डीमैट खातों में तेजी और म्युचुअल फंड कंपनियों के पास मौजूद परिसंपत्ति में तेजी भी इसका प्रमाण है। हालांकि कुल मिलाकर पैसा अलग-अलग श्रेणियों में रहकर तंत्र में ही बना हुआ है। इसका अर्थ यह है कि बैंकों को विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तरह जमा के अलावा बाजार से रकम जुटानी होगी। कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार के विकास के लिए हरसंभव प्रयास किए जाने चाहिए।

अंत में हर किसी के पास बचाने को पैसे नहीं हैं। भारत में परिवारों की शुद्ध वित्तीय बचत घटकर वित्त वर्ष 2023 में 14.2 लाख करोड़ रुपये रह गई, जो पांच साल में सबसे कम थी। वित्त वर्ष 2022 में यह 17.1 लाख करोड़ रुपये थी। वित्त वर्ष 2023 में परिवारों की शुद्ध वित्तीय बचत घटकर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की 5.3 फीसदी रह गई, जो पांच दशकों में सबसे कम है। वित्त वर्ष 2012 और वित्त वर्ष 2022 के बीच (कोविड-19 वाले वित्त वर्ष 2021 को छोड़कर) शुद्ध वित्तीय बचत जीडीपी की औसतन 7-8 फीसदी रही।

स्विस बैंक यूबीएस की एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय परिवार कम अय, ज्यादा खर्च और बढ़ते कर्ज के कारण कम बचत कर पा रहे हैं। देश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में नीचे के 20 फीसदी परिवार लगभग 80 फीसदी रकम खाने-पीने, ईंधन, बिजली और कपड़े पर खर्च करते हैं। इस समस्या का समाधान समावेशी वृद्धि में ही है।

यह स्तंभ में रवींद्रनाथ ठाकुर की एक कविता में दिए गए किस्से के साथ खत्म कर रहा हूं। नंगे पांव चल रहे एक राजा की इच्छा थी कि रास्ते की धूल उनके पांवों पर नहीं लगे। लेकिन ऐसा हो कैसे? पहले सफाई कर्मचारियों ने सड़क साफ की मगर धूल उड़ने से राजा बीमार पड़ गया। इसके बाद कसाइयों ने गाय-बकरी मारनी शुरू कर दीं ताकि पूरी सड़क ढकने के लिए चमड़ा मिल जाए मगर यह तरकीब भी नाकाम रही। आखिरकार राजा के दरबार में एक मोची आया और राजा के पांव का नाप लेकर एक जोड़ी चप्पल बना दी। समस्या हल हो गई। हमें पता है कि क्या करना चाहिए। तो क्या हमें गलत दिशा में निशाना लगाना बंद नहीं करना चाहिए?

आपका पक्ष

भ्रष्टाचार के ढहते पुल

बारिश के मौसम में कुछ राज्यों में पुलों के ढहने की खबरें आई हैं। बिहार के छपरा और महाराजगंज में पुल और पुलिया ढहने की खबर है। पिछले साल बिहार के भागलपुर में लगभग 1,700 करोड़ रुपये का निर्माणाधीन पुल ढह गया था। मुंबई में कुछ साल पहले छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के पास फुटओवर ब्रिज गिरने से कुछ लोगों की मौत हो गई थी। सरकार पुल ढहने के बाद जांच कमेटियां बना कर इतिश्री कर लेती है। अगर देश में निष्पक्ष और उचित जांच की जाए तो ऐसे बहुत से पुलों का आंकड़ा सामने आएगा जो अपनी अंतिम सांस गिन रहे होंगे। भविष्य में पुल हादसे न हो इसके लिए सरकार को हर पुल की जांच करनी चाहिए। वहीं नए पुल के निर्माण पर कड़ी नजर रखनी चाहिए। अगर लापरवाही बरतने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाए तो देश में भ्रष्टाचार और लापरवाही पर लगाम लग सकती है।

राजेश कुमार चौहान, जालंधर

बिहार में पिछले कुछ माह में निर्माणाधीन पुल के साथ कुछ पुराने पुल भारी बारिश के बाद नदियों में जलस्तर बढ़ने के कारण ध्वस्त हो गए

सामरिक व आर्थिक हित होंगे प्रभावित

बांग्लादेश संकट के कारण एक घनिष्ठ, विश्वासपात्र, हितैषी मित्रवत सरकार खो देने से हमारे सामरिक व आर्थिक हित प्रभावित हो सकते हैं। शेख हसीना सरकार के जाने के बाद संभवतः सांप्रदायिक इस्लामिक ताकतें दोनों देशों के आपसी सद्भाव को बढ़ावा न दे पाए। भारत की सुरक्षा संबंधी चिंताओं को समझते हुए आतंकवाद से निपटने के लिए बांग्लादेश से मिलने वाला सहयोग भी प्रभावित हो सकता है। दोनों देशों के घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों को भी हानि पहुंचना संभावित है।

हार्दिक जैन, इंदौर

हमारे घनिष्ठ संबंधों पर विपरीत प्रभाव संभावित

कूटनीतिक संबंध हो या आर्थिक रिश्ते बांग्लादेश के घटनाक्रम का सबसे अधिक विपरीत प्रभाव हमारे देश पर ही होगा। विगत कई वर्षों से बांग्लादेश की लोकतांत्रिक सरकार ने भारत की सुरक्षा व्यवस्था को सदैव गंभीरता से लेते हुए सीमा सुरक्षा पर ध्यान दिया है। आतंकवाद से निपटने में भी हरसंभव मदद की है। जहां तक आर्थिक रिश्तों की बात है दोनों देशों के बीच घनिष्ठ द्विपक्षीय व्यापार समझौते के अंतर्गत अरबों डॉलर का आयात निर्यात भी हुआ है जिसका अब प्रभावित होना अवश्यसंभावी है।

राजश्री जैन, आष्टा

भारत के लिए अनुकूल नहीं रहेंगे रिश्ते

बांग्लादेश में लोकतांत्रिक सरकार के अभाव में तथा शेख हसीना का भारत में शरण लेने से निश्चित ही दोनों देशों के बीच आपसी संबंध बहुत अनुकूल नहीं होंगे। वहां के हिंदू एवं अन्य अल्पसंख्यक वर्गों का भारत में घुसपैठ की कोशिश करना भारत के लिए चिंताजनक है क्योंकि मणिपुर में शांति बहाली में देरी का एक बड़ा कारण म्यांमार के घुसपैठिए भी है और वहां भी लोकतांत्रिक सरकार नहीं है। हालांकि बांग्लादेश की कोई भी सरकार भारत से दूरी बनाकर नहीं रह सकती क्योंकि दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संबंध बहुत प्रगाढ़ है तथा आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक हित भी एक दूसरे से बहुत गहरे स्तर पर जुड़े हुए हैं।

भोगेंद्र कुमार सिंह, दरभंगा

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिज़नेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

देश-दुनिया

फोटो - पीटीआई

सोमवार को संसद भवन परिसर स्थित बाबा साहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा के समक्ष 'ग्लोबल साउथ' देशों के स्वास्थ्य क्षेत्र के नीति निर्माताओं एवं विशेषज्ञों के साथ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा।